

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2634  
उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

**कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

†2634. श्री पुट्टा महेश कुमार:  
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:  
श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश के और विशेषकर आंध्र प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीएआई) के कार्यान्वयन के बारे में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे देश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों (पुरुष, महिला और अन्य) की राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार (विशेषकर एलुरु, कोनासीमा और नेल्लोर जिलों में) कुल संख्या कितनी है;

(ग) पूरे देश में सीबीएआई के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार (विशेषकर एलुरु, कोनासीमा और नेल्लोर जिलों में) आवंटित की गई, स्वीकृत की गई, जारी की गई और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है;

(घ) पूरे देश में सीबीएआई के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार (विशेषकर एलुरु, कोनासीमा और नेल्लोर जिलों में) डिजिटल और संस्थागत अवसंरचना प्रदान किए गए उच्च शिक्षण संस्थाओं की सूची क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पूरे देश में सीबीएआई के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रचार गतिविधि/अभियान चलाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शुरू की है। एनईपी 2020 में सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए प्रासंगिक चरणों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजाइन

थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरणीय शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी), आदि जैसे समकालीन विषयों की शुरुआत की परिकल्पना की गई है।

एनईपी के उद्देश्यों के अनुरूप और तकनीकी शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने आईटी कार्यक्रमों में एआई से संबंधित विषयों को जोड़ा है। गैर-कंप्यूटर विज्ञान शाखाओं जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए उनके क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को एकीकृत करने हेतु विशेष एआई पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। वर्ष 2021 में, एआईसीटीई ने एआई और डेटा साइंस के लिए एक मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया। संकाय को नई प्रौद्योगिकियों के साथ बने रहने में मदद करने के लिए, एआईसीटीई एआई और अन्य उभरते क्षेत्रों में संकाय विकास कार्यक्रम का संचालन भी कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, एआई ज्ञान और कौशल तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से, शिक्षा मंत्रालय के स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आईआईटी, आईआईएससी जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 100 से अधिक निःशुल्क एआई-संबंधित पाठ्यक्रम हैं। इन पाठ्यक्रमों में अब तक 50 लाख से अधिक नामांकन देखे गए हैं।

भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना को भी मंजूरी दी है, जो स्वास्थ्य, दीर्घकालिक शहरों और कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 990.00 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार ने दिनांक 7 मार्च 2024 को "इंडियाएआई" मिशन शुरू किया, जो एक मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक पहल है जो देश के विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। यह मिशन सात आधारभूत स्तंभों अर्थात् - इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर (आईएआईसी), इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (आईएडीआई), इंडियाएआई फ्यूचरस्किल, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पर ध्यान केंद्रित करके भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से संचालित है।

शिक्षा मंत्रालय के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीएआई) शिक्षा में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम संकाय और अकादमिक नेताओं के लिए एआई-संचालित शिक्षा उपकरण विकसित करने और शिक्षण पद्धतियों में सुधार के लिए एआई में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की दिशा में उनकी दक्षताओं को सुदृढ करने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उनकी समग्र गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सुसज्जित करना है। यह कार्यक्रम वर्तमान

में आईआईटी रोपड़ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और संकाय सदस्यों और अकादमिक नेताओं के लिए दो अलग-अलग स्तरों, आधारभूत और उन्नत स्तर के साथ दो श्रेणियों के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम में शैक्षिक सामग्री निर्माण के लिए एआई, प्रशासनिक कार्यों के लिए एआई, एआई शिक्षा का नैतिक उपयोग, कैपस्टोन प्रोजेक्ट और शिक्षा में एआई का भविष्य आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

देश भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का व्यापक कार्यान्वयन और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) पोर्टल ([mmc.ugc.ac.in](http://mmc.ugc.ac.in)) सूचना के प्रसार के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल देश भर के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को कार्यक्रम विवरण और पंजीकरण प्रक्रियाओं पर अपडेट प्रदान करता है, जिससे एक पारदर्शी और सुलभ नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। इस कार्यक्रम के मुख्य पहलुओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी औपचारिक संपर्कों के माध्यम से व्यापक पहुंच भी बनाए रखी जाती है।

\*\*\*